



2026:AHC:55166-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट टैक्स संख्या- 1654 वर्ष 2026

मेसर्स हुमेरा एंटरप्राइजेज याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अजय कुमार यादव, आयुष कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 3

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सरन

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री आर्यन मिश्रा और राज्य-प्रतिपक्षियों के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री निमाई दास को सुना।
2. यू.पी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 129 के तहत पारित दिनांक 10.03.2026 के आदेश को चुनौती दी गई है।
3. निवेदन यह है कि सुनवाई के लिए कोई तारीख तय किए बिना 01.03.2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता 09.03.2026 को प्राधिकरण के समक्ष पेश हुआ और प्रथम दृष्टया उत्तर के साथ लिखित आवेदन दायर किया, लेकिन मुख्य रूप से विस्तृत उत्तर दाखिल करने के लिए संक्षिप्त स्थगन के लिए प्रार्थना की। किसी भी तारीख को सूचित किए बिना, 10.03.2026 को याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया।
4. दूसरी ओर, अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि अधिकारी सात दिनों के भीतर आदेश पारित करने के लिए बाध्य था। इसके बाद, आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, सबसे पहले, 01.03.2026 के कारण बताओ नोटिस में याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने की कोई निश्चित तारीख का खुलासा नहीं किया गया था और इसने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख के बारे में सूचित नहीं किया था। इसने केवल यह सूचित किया कि उत्तर सात दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है।

6. फिर भी, यह तथ्य है या होली के त्योहार ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद, 09.03.2026 को याचिकाकर्ता ने स्थगन आवेदन दायर किया, जिसमें संक्षिप्त स्थगन की मांग की गई। एक बार जब वह आवेदन पेश कर दिया गया, तो याचिकाकर्ता ने सात दिनों के भीतर आदेश सुरक्षित करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया होगा। किसी भी मामले में, स्थगन आवेदन से निपटे बिना, योग्यता के मुद्दे पर आदेश पारित करना कभी भी प्राधिकरण के पास नहीं आया। तीसरा, 09.03.2026 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया। वास्तव में, वह आदेश 10.03.2026 को पारित किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने जिस आदेश में उत्तर प्रस्तुत किया है, वह पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने दिनांक 09.03.2026 के स्थगन आवेदन में कहा था कि वह माल का मालिक है, साथ ही आवेदन के प्रस्तर-संख्या-3 और 7 में विशेष रूप से उचित उत्तर दाखिल करने के लिए और समय देने की प्रार्थना की गई है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने केवल स्थगन की मांग की थी।

7. जिस हद तक, याचिकाकर्ता के मूल्यवान नागरिक अधिकार शामिल हैं और इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने केवल एक स्थगन की मांग की थी, हम पाते हैं, कि उस प्राधिकरण द्वारा अधिकार का उल्लंघन किया गया है, जिसने कार्यवाही में सुनवाई की कोई तारीख तय किए बिना, याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना दिनांक 01.03.2026 का आदेश पारित किया है।

8. ऐसे तथ्यों में, वर्तमान को लंबित रखने या इस स्तर पर जवाबी हलफनामा बुलाने या याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपचार के मंच पर वापस लाने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता है। जिस हद तक कारण बताओ नोटिस इसी महीने जारी किया गया था और उसके बाद दस दिनों के भीतर आदेश पारित किया गया है, हम इसे भारत



के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने सीमित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप की पेशकश करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाते हैं।

9. तदनुसार, दिनांक 10.03.2026 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता दिनांक 01.03.2026 के आदेश सपठित कारण बताओ नोटिस का विस्तृत उत्तर 27.03.2026 तक दाखिल कर सकता है। इस तरह के अनुपालन के अधीन, याचिकाकर्ता 30.03.2026 को सुबह 11:00 बजे प्रतिपक्षी संख्या-2 के समक्ष उपस्थित हो सकता है। इसके बाद, प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा उचित तर्कसंगत आदेश पारित किया जा सकता है।

10. याचिकाकर्ता के लिए यह खुला रहेगा कि वह अस्थायी रूप से जुर्माना राशि जमा करने के खिलाफ माल और वाहन जारी कर सके।

11. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, प्रस्तुत याचिका का निस्तारण किया जाता है।

मार्च 18, 2026

अभिलाष

(न्यायमूर्ति विवेक सरन) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)